भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2903

बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गति शक्ति योजना

2903. श्री डी.के. सुरेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कारोबारी माहौल, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना शुरू की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पीएम गति शक्ति योजना की उपलब्धि जानने के लिए कोई आकलन/समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान (एनएमपी) का शुभारंभ किया। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, केंद्र सरकार के आर्थिक मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न अवसंरचना तथा मुख्य और उपयोगिता अवसंरचना, जारी और भविष्य की परियोजनाओं का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। यह डेटा, जीआईएस-आधारित पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, जिससे एक ही पोर्टल पर अगली पीढ़ी की अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना, डिजाइन और मानीटरिंग की सुविधा मिलती है। वस्त्र क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, कृषि क्षेत्र आदि जैसे आर्थिक क्षेत्रों को एकीकृत अवसंरचना की योजना के लिए मैप किया जा रहा है और भारतीय व्यवसायों को अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी को विज़ुअलाइज करके निवेश को जोखिम से मुक्त करते हुए विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाएगा और निर्यात बाजारों में देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जाएगा।

एकीकृत अवसंरचना के विकास की आवश्यकताओं को जहां पीएम गतिशक्ति एनएमपी के माध्यम से पूरा किया जाता है, वहीं सेवाओं (जैसे प्रक्रियाओं, डिजिटल प्रणालियों और विनियामक फ्रेमवर्क) और मानव संसाधनों में दक्षता संबंधी आवश्यकताओं को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 द्वारा अपनी व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य-योजना (सीएलएपी) के माध्यम से पूरा किया जाता है।

एनएमपी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, दोनों साथ में मिलकर, देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा आधारित निर्णय सहायता प्रणाली बनाने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है।

(ग) और (घ) : पीएम गतिशक्ति सरकार आधारित एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसे संबंधित मंत्रालयों के बीच सहयोग के माध्यम से मल्टीमॉडल अवसंरचना की एकीकृत योजना की सुविधा के लिए अपनाया गया है। अब तक, डीपीआईआईटी के लॉजिस्टिक्स प्रभाग ने अवसंरचना परियोजनाओं के व्यापक क्षेत्र-आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 62 बैठकों का आयोजन किया है।

विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं; अन्य के साथ-साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भूमि सर्वेक्षण, भू-अभिलेख और राजमार्ग एलाइनमेंट के लिए पीएम गतिशक्ति का उपयोग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की योजना बनाने में समय और लागत की बचत हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कम समय में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एनएमपी के इलेक्ट्रॉनिक डिटेल रूट सर्वे (ईडीआरएस) का उपयोग करता है। रेल मंत्रालय ने अंतिम स्थल सर्वेक्षण (एफएलएस) के कार्य को वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में काफी तेजी से अंतिम रूप प्रदान किया है।

इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएम गतिशक्ति संस्थागत तंत्र को अपनाया गया है और शुरु से अंत तक कनेक्टिविटी की कमियों का आकलन करने और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एनपीजी बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

****